गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मन्त्री — वित्त एवं योजना मन्त्री, हरियाणा।

प्रशासकीय सचिव — प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, योजना विभाग ।

विषय :– अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2012–13 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तथा समीक्षा ।

.....

वर्ष 2012–13 के लिये अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (केवल हिन्दी भाषा में) तथा समीक्षा एवं समालोचना (हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में) मुख्य सचिव, हरियाणा के अशा0 क्रमांक 15/19/91–4 पी0पी0 दिनांक 30–3–93 के अनुदेशों के अनुसार मन्त्रीपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

इस मामले को मन्त्रीपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति ले ली गई है ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 05–07–2013

(संजीव कौशल)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2012–13 के कार्य की समीक्षा ।

.....

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग का मुख्य कार्य राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नियोजन एवं प्रशासन हेतू विभिन्न प्रकार के अभीष्ट आंकड़ों को एकत्रित, संकलित एवं विश्लेषण करना है । राज्य के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर सर्वेक्षण करना, मूल्यांकन अध्ययन करना, पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना बनाने में सहायता प्रदान करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना आदि कार्य भी इसी विभाग द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं ।

वर्ष 2012–13 के दौरान सांख्यिकीय सारांश हरियाणा, 2011–12 जिसमें राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत आंकड़े दिये जाते हैं, को तैयार किया गया व बजट सत्र के दौरान विधान सभा में अन्य बजट प्रलेखों के साथ **Softcopy** में विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

'आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा, 2012–13 जिसमें राज्य अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति दर्शाई जाती है, को तैयार किया गया व बजट सत्र के दौरान **Softcopy** में हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया ।

विभाग द्वारा 31 मार्च, 2011 को हरियाणा सरकार के अधीन अमला के आंकड़ों की गणना का कार्य किया गया व विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण सम्बन्धी कार्ड जारी किया गया । इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2012 से सम्बन्धित अमला के आंकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन कार्य भी जारी रहा ।

हरियाणा गजट भाग II में प्रकाशन के लिए मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक नियमित तौर पर (श्रमिक वर्ग) तैयार किया जाता है । इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिक मजदूरी एवं ग्रामीण खुदरा कीमत, चुनी हुई वस्तुओं की खुदरा एवं थोक भाव की मासिक विवरणियां एकत्रित तथा संकलित करके राज्य तथा केन्द्र सरकार को भिन्न–भिन्न प्रकार की रिपोर्ट एवं सूचना प्रेषित की गई ।

प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय अनुमान वर्ष 2010–11 के लिये तैयार किये गये। वर्ष 2011–12 के द्रुत अनुमान तथा वर्ष 2012–13 के अग्रिम अनुमान भी प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर तैयार किये गये ।

हरियाणा राज्य के जिला स्तरीय सकल एंव निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय अनुमान नई श्रृंखला आधार वर्ष (2004–05) वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर तैयार किए गए।

"हरियाणा सरकार के बजट वर्ष 2012–13 का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण" तथा "राज्यों के वित्त का विश्लेषण वर्ष 2011–12" नामक प्रतिवेदनों को तैयार किया गया तथा "हरियाणा राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2010–11" को तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा ।

वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित "कृषि लेखा" व "कृषि परिवार बजट" नामक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई व वर्ष 2011–12 से सम्बन्धी कार्य प्रगति पर रहा।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक (आधार वर्ष 2004–05) तैयार किया गया ।

सन्दर्भाधीन अवधि में स्थानीय स्तर विकास के लिए मूलभूत आंकड़े व राष्ट्रीय भवन संगठन का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर रहा ।

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के 68 वें व 69 वें दौर का कार्य सम्पूर्ण करवाया गया।

तीन जिलों में प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न विभागों के 94 कर्मचारियों को प्राथमिक सांख्यिकी सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा विभाग के लगभग 29 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया ।

सभी जिलों के वर्ष 2010–11 के जिला सांख्यिकीय सारांश, सामाजिक–आर्थिक पुननिरीक्षण तथा नगरपालिका वार्षिक पुस्तक को तैयार किया गया ।

वर्ष 2012–13 के दौरान वार्षिक योजना 2013–14 व 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का प्रारूप भी तैयार किया गया।

वर्ष 2012–13 के दौरान जिला योजना स्कीम के तहत राज्य के सभी जिलों को राशि जारी की गई ।

राज्य स्ट्रैटजिक सांख्यिकीय योजना (SSSP) व 13वां वित्त आयोग (TFC) से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर रहा ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारन्टी स्कीम, मिड डे मील, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं इन्दिरा आवास योजना की मूल्यांकन रिर्पोटें मुद्रित करवाने उपरान्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी गई।

20–सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिर्पोट का नियमित रूप से अनुश्रवण किया गया तथा वांछित सूचना भारत सरकार को भेजी गई ।

जिला सांख्यिकीय एजैंसियां अपने जिलों के जिला सांख्यिकीय सारांश, जिला सामाजिक आर्थिक पुननिरीक्षण, नगरपालिका वार्षिक पुस्तक तैयार करने/संशोधन करने में तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यकलापों में व्यस्त रहीं ।

दिनांकः चण्डीगढ 05–07–2013

संजीव कौशल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2012–13

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, योजना विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्य करता है।

इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार वर्णित हैं :–

(क) राज्य के विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं पर आंकड़ों का संग्रह, संकलन तथा उनका विश्लेषण ।

(ख) राज्य के योजना एवं विकास कार्यक्रमों के निरूपण हेतु अपेक्षित आंकडों को जुटाना ।

(ग) राज्य की विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं से सम्बन्धित समस्याओं का सर्वेक्षण करना ।

(घ) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों का समन्वय करना ।

(ड) राज्य सरकार को आर्थिक एवं सांख्यिकीय विषयों पर परामर्श देना ।

(च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (भारत सरकार) तथा अन्य राज्यों के सांख्यिकीय विभागों के साथ सम्पर्क करके कार्य करना ।

(छ) विकास योजनाओं /परियोजनाओं /स्कीमों का मूल्याकंन करना ।

(ज) पंचवर्षीय योजना /वार्षिक योजनाओं को बनाना तथा उनका कार्यान्वयन ।

(झ) जिला योजना के अन्तर्गत जिला स्तर की योजनाओं को बनाना तथा उनका कार्यान्वयन ।

(न) 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करना ।

(ट) विभिन्न विभागों की मानवशक्ति एवं रोजगार गतिविधियों का समन्वय करना तथा मानवशक्ति एवं रोजगार प्रदान करने वाली परियोजनाओं का अध्ययन करना ।

उपर्युक्त गतिविधियों से विदित होता है कि अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा मुख्यतः एक अनुसंधान विभाग है जो कि समय–समय पर नियमित तथा तदर्थ आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण/अध्ययन करता है । इस प्रकार इस विभाग के कोई भौतिक लक्ष्य अथवा उपलब्धियां नही होती हैं । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा हरियाणा सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, राज्यों के बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनवार कार्यात्मक वर्गीकरण, हरियाणा में नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण, हरियाणा में कृषि की आर्थिक–व्यवस्था का अध्ययन तथा हरियाणा में कृषकों का परिवार बजट सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे कई वार्षिक प्रकाशन नियमित आधार पर मुद्रित करवाए जाते हैं ।

इस विभाग में आर्थिक तथा योजना प्रभागों के अन्तर्गत क्रमशः निम्नलिखित अनुभाग कार्य कर रहे हैं :–

(क) सांख्यिकीय प्रभाग

1 संग्रह तथा संकलन

2 कीमत

3 राज्य आय

4 लोक वित्त

5 क्षेत्रीय लेखा

6 पूंजी निर्माण

7 कृषि

8 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण एवं सारणीकरण

9 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

10 प्रशिक्षण

11 सामाजिक सांख्यिकीय सुधार

13 आर्थिक सर्वेक्षण

14 सर्वेक्षण अनुभाग

15 राज्य स्ट्रटेजिक सांख्यिकीय योजना (SSSP) अनुभाग

(ख) योजना प्रभाग

15 योजना निरूपण तथा कार्यान्वयन

16 जिला योजना

17 मूल्यांकन सर्वेक्षण

18 योजना अनुश्रवण

19 मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय

20 राज्य पदर्शन प्रबन्धन सैल (आर0एफ0डी0)

वर्ष 2012–13 के दौरान अनुभागों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) सांख्यिकीय प्रभाग

1 संग्रह तथा संकलन अनुभाग

यह अनुभाग मुख्यतः राज्य के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर सांख्यिकीय सामग्री का संग्रह तथा संकलन करके इनका नियमित रूप से प्रकाशन करवाता है ।

इस अनुभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों से विभिन्न विभागों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/अनुसंधान–कर्ताओं की दिन प्रतिदिन की सांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है । राज्य सांख्यिकीय सारांश को तैयार करना अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा का एक वार्षिक कार्य है । तदानुसार वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 के सांख्यिकीय सारांश को समय पर तैयार किया गया । इस दस्तावेज को बजट सत्र (बजट सैशन) के दौरान अन्य बजट प्रलेखों के साथ विधायकों को **Softcopy** के रुप में वितरित किया गया । इस दस्तावेज में नीति निर्णय लेने, विकास योजनाओं के निरूपण तथा अनुसंधान कार्यों हेतु लगभग सभी महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं विशेषकर क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, लोक वित्त, कीमत सूचकांक, राज्य आय आदि के आंकड़ों का समावेश किया जाता है । ये आंकड़े राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को जानने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं । यह इस विभाग का महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है, जिसकी मांग गत वर्षो की तुलना में बढती जा रही है ।

केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त सांख्यिकीय सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा वर्ष 1967 से प्रति वर्ष कर्मचारी वर्ग की गणना से सम्बन्धित आवश्यक सूचना एकत्रित कर रहा है । इस सूचना का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में नीति निर्धारण हेतु तथा कर्मचारियों को अन्य वित्तिय सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाता है । संदर्भाधीन अवधि के दौरान हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में कार्यरत अमला के आकंड़े संदर्भ तिथि 31 मार्च, 2011 से सम्बन्धित परिणामों को अन्तिम रूप दिया गया व कार्ड मुद्रित करवाया गया तथा 31 मार्च, 2012 से सम्बन्धित अमला के आकंडों का संग्रह एवं सकंलन का कार्य प्रगति पर रहा ।

कृषि श्रमिक मजदूरी तथा ग्रामीण खुदरा भावों की सूचना मास फरवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक एकत्रित तथा संकलित करके कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई ।

2 कीमत अनुभाग

यह अनुभाग साप्ताहिक खुदरा भाव, पाक्षिक ग्रामीण भाव, कृषि वस्तुओं के थोक भाव तथा त्रैमासिक मकान किराया सर्वेक्षण से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करता है व कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक, ग्रामीण खुदरा भाव सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में मास फरवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100), जो कि छः केन्द्रों नामतः भिवानी, हिसार, सोनीपत, सूरजपूर–पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत एवं हरियाणा राज्य के लिए संकलित करके गजट अधिसूचना के रुप में जारी किए गए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की हैसियत से जनवरी, 2012 से जून, 2012 तक तथा जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक के छः माही श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता कीमत सूचकांक छः चुने हुए केन्द्रों तथा श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा संकलित यमुनानगर व फरीदाबाद केन्द्रों के उपभोक्ता कीमत सूचकांकों की घोषणा की गई तथा गजट अधिसूचना जारी की गई ।

फरवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक के कृषि उत्पादों के थोक भावों के सूचकांक (आधार वर्ष 1980–81=100) तैयार किये गये ।

ग्रामीण खुदरा भावों की जांच करके मास मार्च, 2012 से फरवरी, 2013 तक का सकंलन कार्य किया गया तथा फरवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक के सूचकांक तैयार किये गये ।

त्रैमासिक मकान किराया सर्वेक्षण से सम्बन्धित तिमाही मार्च, जून, सितम्बर, तथा दिसम्बर, 2012 की प्राप्त अनुसूचियों की छानबीन करके मकान किराये का सूचकांक तैयार किया गया।

प्राईस मोनिटरिंग सैल के लिए मास अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक कीमतों की समीक्षा तैयार करके निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा को भेजी गई ।

परिवार आय –व्यय सर्वेक्षण से सम्बन्धित सूचना को तैयार करने का कार्य प्रगति में रहा।

3 राज्य आय अनुभाग

राज्य आय अनुभाग हरियाणा राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान तथा प्रति व्यक्ति आय अनुमान प्रचलित तथा स्थिर भावों पर नियमित तौर पर तैयार करता है । ये अनुमान राज्य के आर्थिक विकास के माप के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं । आर्थिक विकास दर्शाने के साथ–साथ क्षेत्रवार अनुमान राज्य की अर्थ–व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हें । राज्य आय अनुभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्न कार्य किए गए :–

पुरानी श्रृंखला आधार वर्ष 1999–2000 पर आधारित अपनाई गई रीति विधान सम्बन्धी रिपोर्ट वर्ष 2008–09 व नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004–05 पर आधारित हरियाणा राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों एवं उन्हें तैयार करने के लिये अपनाई गई रीति विधान सम्बन्धी रिपोर्ट वर्ष 2009–10 व 2010–11 तैयार की गई व मुद्रण करवाया गया ।

नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004–05 पर आधारित हरियाणा राज्य के सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर वर्ष 2008–09 से 2009–10 (संशोधित), वर्ष 2010–11 (अनन्तिम), वर्ष 2011–12 (द्रुत) तथा 2012–13 (अग्रिम) तैयार किए गए ।

हरियाणा राज्य के जिला स्तरीय सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय, के अनुमान नई श्रृंखला आधार वर्ष (2004–05) पर वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर तैयार किए गए ।

वर्ष 2011–12 के राज्य आय अनुमान तैयार करने के लिए सूचना का एकत्रीकरण तथा संकलन कार्य प्रगति पर रहा।

4 लोक वित्त अनुभाग

लोक वित्त अनुभाग "हरियाणा सरकार के बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण" तथा "राज्यों के वित्त का विश्लेषण" नामक प्रतिवेदन वार्षिक आधार पर तैयार करता है।

हरियाणा सरकार के बजट वर्ष 2012–13 की आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार की गई। राज्यों के वित्त का विश्लेषण **(An Analysis of State Finances-2011–12)** रिपोर्ट तैयार की गई। वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 (स.अ.) की विस्तृत तथा संकलित सूचना तैयार की गई तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली को प्रेषित की गई।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली द्वारा वांछित पूर्ति प्रयोग तालिकायें वर्ष 2009–10 **(Supply Use Tables)** से सम्बन्धित सूचना तैयार की गई।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना वर्ष 2004–05 से 2011–12 (स.अ.) तक की सहायता अनुदान (सब्सिडी) व अप्रत्यक्ष करों का मदवार विवरण तैयार किया गया।

5 क्षेत्रीय लेखा अनुभाग

क्षेत्रीय लेखा अनुभाग हरियाणा राज्य की नगरपालिकाओं /परिषदों/ निगमों के बजटों का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार करता है । इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य की ग्राम पंचायतों के बजट (ब्लाक वार) तथा पंचायत समितियों के बजटों की सूचना का एकत्रीकरण व संकलन कार्य करता है ।

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य की सभी नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों तथा सभी ग्राम पंचायतों (खण्ड स्तर) के वर्ष 2010–11 के बजटों का एकत्रीकरण एवं संकलन कार्य प्रगति पर रहा।

6 पूंजी निर्माण अनुभाग

पूंजी निर्माण अनुभाग राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वार्षिक आधार पर तैयार करता है। सकल स्थाई पूंजी निर्माण भौतिक रूप में पुनः उत्पादन योग्य वस्तुओं के उत्पादकों की परिसम्पतियों जिनकी उपभोग की अनुमानित अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो, में बढ़ोतरी को दर्शाता है। इन अनुमानों का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पतियों पर प्रतिवर्ष कितना निवेश किया जा रहा है। इस अनुभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में किये गये कार्य निम्नलिखित है :–

सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2004–05 से 2010–11 तक प्रचलित व स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर उद्योगों के उपयोग, संस्थानुसार तथा परिसम्पतियों के प्रकारानुसार तैयार किए गए।

स्कल स्थाई पूंजी निर्माण, हरियाणा की रिपोर्ट वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 तक (आधार वर्ष 2004–05) पर तैयार करके मुद्रित करवाई गई।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2011–12 के लिए सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर रहा व प्राप्त सूचना की छानबीन की गई।

7 कृषि अनुभाग

कृषि अनुभाग प्रति वर्ष नियमित तौर पर दो प्रतिवेदन नामतः "हरियाणा में कृषकों की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन" एवं "कृषकों के परिवार बजट अध्ययन" तैयार करता है । कृषकों की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन रिपोर्ट में राज्य के चुने हुये कृषकों की जोतों की विभिन्न फसलों के उत्पादन, लागत तथा आय का अध्ययन किया जाता है । "कृषकों के परिवार बजट अध्ययन" के अन्तर्गत राज्य के चुने हुए कृषक परिवारों की आय तथा व्यय का विश्लेषण किया जाता है ।

"कृषि लेखा अध्ययन" रिपार्ट तथा "कृषि परिवार बजट अध्ययन" रिपोर्ट वर्ष 2010–11 तैयार की गई व वर्ष 2011–12 से सम्बन्धी कार्य प्रगति पर रहा ।

कृषि सूचकांक नई सीरिज में आधार त्रैवर्षान्त 2007–08 के तहत विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व ऊपज सूचकांक को तैयार किया गया ।

8 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं सारणीकरण अनुभाग

यह अनुभाग भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सहयोग से क्षेत्रीय सर्वेक्षण करता है । इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में भूमि उपयोगिता, ऋण तथा निवेश, विनिर्माण, घरेलू मकानों की दशा, उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार एवं बेरोजगारी तथा व्यापार आदि कई सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर सूचना एकत्रित की जाती है ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68 वें दौर के तृतीय व चतुर्थ उपचरण ग्रामीण क्षेत्र के 63 सैम्पल व शहरी क्षेत्र के 50 सैम्पल का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया । उक्त अवधि के दौरान 69 वें दौर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 76-76 सैम्पलों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 70 वें दौर से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रशिक्षण सभा का आयोजन एन0एस0एस0ओ0, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया व 69 वें दौर से सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशिक्षण सभा मास जून, 2012 में एन0एस0एस0ओ0, हरियाणा सर्कल, चण्डीगढ द्वारा आयोजित की गई जिसमे अधिकारीयों व कर्मचारियों ने भाग लिया ।

सभी सातों सर्कलों में **NSS** के 66वें दौर के **Data Entry** एवं **Validation** के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला सांख्यान कार्यालय, नारनौल व रोहतक में **NSS** का कार्य कर रहे **Data Entry operator** के कार्य को चैक किया और उस दौरान आई कठिनाईयों को दूर करवाया गया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 64वें दौर की अनुसूचि 10.2 की **migration** से सम्बन्धित तालिकाएं तैयार की गई। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 64वें चरण की 10.2 रोजगार तथा बेरोजगारी से समबन्धित रिपोर्ट तैयार करके मुद्रित करवाई गई।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, कोलकाता द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 66वें चरण की सारणीकरण से सम्बन्धित कार्यशाला में भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित **NSS** के 67वें चरण की **Data Processing** से सम्बन्धित कार्यशाला में भाग लिया ।**NSS** के 67वें दौर की भरी हुई अनुसूचियों को जिला कार्यालयों से प्राप्त होने उपरान्त **Validation** का कार्य मुख्यालय स्तर पर शुरू किया गया।

9 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग

यह अनुभाग हरियाणा राज्य के मासिक एवं वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करता है। ये सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति तथा औद्योगिक क्षेत्र में आए मूलभूत परिवर्तनों को दर्शाते हैं ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) पर वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक की रिपोर्ट तैयार की गई। मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) पर मास अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक तैयार किया गया। वर्ष के दौरान वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) पर वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक तैयार किया गया।

उक्त अवधि के दौरान मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मास अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 (आधार वर्ष 2004–05) तक तैयार करने हेतु चयन की गई औद्योगिक इकाईयों से उत्पादन सम्बन्धी सूचना एकत्रित, छानबीन व संकलन करने का कार्य प्रगति पर रहा।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2011–12 सम्बन्धी आल इण्डिया ट्रेनिंग, कोलकाता में अधिकारियों ने भाग लिया ।

10 प्रशिक्षण अनुभाग

यह अनुभाग विभिन्न विभागों के मध्य/निचले स्तर के सांख्यिकीय कर्मचारियों के लिये जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है । प्रशिक्षण का उद्देश्य इन कर्मचारियों को सांख्यिकीय सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान जैसे आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण तथा प्रस्तुतीकरण आदि से परिचय करवाना है। प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य के बारे भी अवगत कराया जाता है ।

वर्ष 2012–13 के दौरान जिला स्तर पर तीन जिलों नामत्ः फरीदाबाद, पलवल तथा यमुनानगर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के 94 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त विभाग के लगभग 29 अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद व अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतू भेजा गया । इसके अतिरिक्त **"Citizen Charter-2012"** भी तैयार किया गया ।

11 सामाजिक सांख्यिकीय सुधार अनुभाग

यह अनुभाग राज्य में लोगों के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक–आर्थिक सूचकों को तैयार करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सांख्यिकीय सारांश 2011–12 में सम्मिलित करने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न सूचक तैयार किए गए ।

12 आर्थिक सर्वेक्षण अनुभाग

हरियाणा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13 जिसमें अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति दर्शाई जाती है, को तैयार कर बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया ।

13 सर्वेक्षण अनुभाग

यह अनुभाग विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का कार्य करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए सर्वेक्षण कार्यों का विवरण निम्न अनुसार हैः–

क स्थानीय स्तर विकास के लिए मूलभूत आंकड़े

उक्त सर्वेक्षण हरियाणा राज्य के 2 जिलों नामतः कुरूक्षेत्र व पंचकूला में करवाया गया है। उक्त सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा 100% केन्द्रीय प्रायोजित सर्वेक्षण है। उक्त अवधि में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है व Data Entry का कार्य पूर्ण किया गया व रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा।

ख राष्ट्रीय भवन संगठन

उक्त सर्वेक्षण आवास एंव शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की स्कीम के तहत शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के तहत सभी जिलों में वर्ष 2007–08 से सूचना राज्य के सभी जिलों से नियमित तौर पर एकत्रित की जा रही है व भारत सरकार को online भेजी जा रही है।

ग हरियाणा के अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षणः

उक्त सर्वेक्षण सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सोसाइटिज एक्ट–1860 के अर्न्तगत दर्ज भारत में अलाभकारी संस्थाओं के लेखों का कम्पयूटरीकरण तथा उनसे सम्बन्धित लेखे तैयार करने का प्रौजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रौजेक्ट का कार्य हरियाणा में अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग को दिया गया। उक्त अध्ययन दो चरणों में पूर्ण किया जाना थाः–

क प्रथम चरणः–

जिला उघोग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों से संस्थाओं की जिलावार सूची तैयार करना।

ख द्वितीय चरणः–

संस्थाओं से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र अनुसार भौतिक व वित्तीय आंकड़े एकत्रित करना।

तदानुसार सर्वे के पहले चरण में सोसाइटिज एक्ट–1860 के तहत अलाभकारी संस्थाओं की सूची तैयार की गई।

सर्वे के द्वितीय चरण में दस जिलों नामतः पंचकुला, कुरूक्षेत्र, हिसार, जीन्द, करनाल, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद तथा महेन्द्रगढ में सर्वेक्षण कार्य करवाया गया। सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात डाटा की छानबीन कर कम्पयूटराईज किया गया व केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया व रिर्पोट तैयार की गई ।

14 राज्य स्ट्रटेजिक सांख्यिकीय परियोजना (SSSP) अनुभाग

सांख्यिकीय एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक "भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ परियोजना" नामक परियोजना आरम्भ की गई है। उक्त परियोजना भारत सरकार को विश्व बैंक द्वारा वित्तिय सहायता स्कीम के तहत शुरू की गई है जोकि इस परियोजना के अधीन राज्यों को ग्रांट–इन–एड के रूप में फण्ड जारी किए जाएगें। इस परियोजना के तहत हरियाणा राज्य में "राज्य स्ट्रटेजिक सांख्यिकीय योजना" लागू की गई है व इसके लिए भागीदारी का पत्र (LOP) व उच्च स्तरीय सटियरिंग कमेटी (HLSC) का गठन किया जा चुका है।

नोडल विभाग द्वारा (अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग) एक ड्राफ्ट रिर्पोट तैयार की जा रही है जिसमें स्टेक होल्डरज व Line departments से inputs लेकर फन्डों के वितरण के कार्य बारे विस्तृत कार्यवाही की जा रही है। रिर्पोट को अन्तिम रूप देने के पश्चात मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में होने वाली HLSC की बैठक में रिर्पोट को पेश किया जाएगा। रिर्पोट के अनुमोदन उपरान्त इसे अन्तिम अनुमोदन हेतु एंव फण्ड जारी करने हेतु भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।

(ख) <u>योजना प्रभाग</u>

15. योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन अनुभाग

यह अनुभाग राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं तैयार करता है तथा योजना अवधि में योजना स्कीमों के कार्यान्वयन पर नजर रखता है ।

विभिन्न विभागों से वार्षिक योजना 2012–13 से सम्बन्धित अतिरिक्त परिव्यय/आपस में स्कीमों के परिवर्तन के लिये प्राप्त राशि प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त विभागों को आवश्यक परामर्श जारी किये गये । विभिन्न विभागों से प्राप्त नई परियोजनाओं की समीक्षा करने उपरान्त **Standing Finance Committee** की बैठक आयोजित करवाई गईं । दिनांक 11–4–2012 को डा0 अश्विनी कुमार, राज्य योजना मंत्री, डा0 जे0एस0 शर्मा, सी0ई0ओ0 तथा सम्बन्धित वरिष्ठ सलाहकार के चण्डीगढ़ दौरे के दौरान वर्ष 2011–12 के फलैगशिप कार्यक्रमों तथा हरियाणा की प्रस्तावित वार्षिक योजना 2012–13 की समीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार करने उपरान्त बैठक आयोजित करवाई गई ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तथा वार्षिक योजना 2012–13 का प्रस्तावित योजना परिव्यय निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय तथा सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 25–4–2012 को आयोजित वर्किंग ग्रुप मीटिंग से सम्बन्धित दस्तावेज तथा पावर प्वाइंट प्रेजैन्टेशन तैयार कर योजना आयोग, नई दिल्ली में बैठक करवाई गई । बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तथा वार्षिक योजना 2012–13 का योजना परिव्यय अनुमोदित करने हेतु मुख्य मन्त्री महोदय तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में योजना आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 30–4–2012 को आयोजित बैठक के लिए आवश्यक दस्तावेज, पावर प्वाइंट प्रेजैन्टेशन तथा मुख्य मंत्री का अभिभाषण तैयार किया गया एवं बैठक आयोजित करवाई गई।

विकास कार्यक्रमों, विशेष तौर पर फ्लैगशिप कार्यक्रमों के संचालन हेतु, विभिन्न जिलों के उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, योजना अधिकारियों एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु पत्र प्रेषित किए गए ।

Central Sector Project Coordination Committee (CSPCC) के अन्तर्गत होने वाली बैठक में विचार–विमर्श हेतु हरियाणा राज्य में लागू की गई विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची मंगवाने के लिए भारत सरकार को पत्र जारी किए गए । अनुमोदित वार्षिक योजना 2012–13 के क्षेत्रीय विभाजन निर्धारित कर विभिन्न विभागों को भेजा गया । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि का विभिन्न विभागों में बंटवारा किया गया एवं सम्बन्धित विभागों से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा मंगवाकर, समीक्षा व विश्लेषण करने उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार को भेजा गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए **ISS Probationer** के समक्ष योजना प्रक्रिया पर तैयार की गई स्लाइड प्रैजैन्टेशन प्रस्तुत की गई । बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 6 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में राज्यों के साथ भाग लेने हेतु योजना प्रक्रिया के बारे में सूचना तैयार की गई । प्रस्तावित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न विभागों से एकत्रित की गई सूचना को संकलित किया गया तथा योजना आयोग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया ।

मुख्य सचिव के समक्ष समाज की वॉलनटियर एजैन्सियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, एम0एन0जी0ओ0 निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया । हरियाणा की वार्षिक योजना 2012–13 को अन्तिम रूप देने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा मुख्य मन्त्री, हरियाणा के बीच योजना आयोग, नई दिल्ली में की गई बैठक का संक्षिप्त विवरण, सम्बन्धित विभागों को सूचित करने तथा उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भेजा गया । दिनांक 27–7–2012 को प्रधान सचिव, योजना विभाग की अध्यक्षता में वार्षिक योजना 2011–12 के अन्तर्गत किए गए व्ययों के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई । मुख्य विभागों से सम्बन्धित हरियाणा सरकार की विशेष योजनाओं तथा सफलता की कहानियां एकत्रित करने पश्चात् योजना आयोग, भारत सरकार को भेजी गई । कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा तैयार की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली **Budgetary Assumption** की समीक्षा हेतु सम्बन्धित विभागों से सूचना मंगवाने का कार्य प्रगति पर रहा। सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचना की समीक्षा करके सीनियर ऑडिट ऑफिसर, प्रिंसिपल एकाउंटैंट जनरल (ऑडिट) कार्यालय को प्रेषित की गई तथा जिन विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई, उन्हें स्मरण पत्र जारी किए गए ।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा मांगी गई बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के लिए सम्बन्धित विभागों से लक्ष्यों की सूची एकत्रित करने पश्चात व समीक्षा उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार को भेजी गई। हरियाणा राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के दौरान विचार–विमर्श किए गए पहलुओं के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से **Action Taken Report** मंगवाई गई तथा शिक्षा विभाग को **High Level Task Force** गठित करने व **Action Taken Report** भेजने के लिए लिखा गया । प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14 तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुमानित सूचना मंगवाई गई । प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14 के लिए विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत, आवंटन को निर्धारित करने के लिए सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करवाई गईं । वर्ष 2012–13 के दौरान 'अनुसंधान एवं विकास हेतु संस्थान' नामित एक नई योजना के अन्तर्गत रिसर्च इन्स्टीट्यूशनज़ को अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए तथा विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकन करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति की आमंत्रणा की गई । एन्वायरमैंट प्रफॉरमैंस इन्डैक्स के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की गई तथा समीक्षा उपरान्त योजना आयोग, भारत सरकार को भेजी गई ।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय व विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हेतु विभिन्न विभागों से मुद्दे मंगवाकर मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण तथा सम्बन्धित दस्तावेज तैयार किए गए । बारहवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित 9 विभिन्न क्षेत्रों के वर्किंग ग्रुप गठित किए गए तथा उनके **Terms of Reference** निर्धारित किए गए । इसके उपरान्त सम्बन्धित विभागों को वर्किंग ग्रुप की बैठके करवाने तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए । वार्षिक योजना 2012–13 के **OTACA release** करने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार को पत्र लिखा गया । इस संदर्भ में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लगाए गए **objections** का निपटान किया गया तथा **ACA** की शेष राशि **release** करवाई गई । प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14 के अन्तर्गत क्षेत्रीय आबंटन निर्धारित करने उपरान्त विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मंगवा कर उनकी समीक्षा की गई । वार्षिक योजना 2012–13 के संशोधित परिव्यय, वार्षिक योजना 2013–14 के प्रस्तावित परिव्यय तथा **SCSP Component** अनुमोदित करवा कर सम्बन्धित विभागों को पत्र जारी किए गए तथा स्कीमवार विवरण मंगवाई गई ।

विभिन्न विभागों से वार्षिक योजना 2013–14 को अन्तिम रूप देने हेतु बैठक में मुख्य मंत्री के भाषण व **Slide Presentation** हेतु विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मंगवाए गए । प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14 को अन्तिम रूप देने उपरान्त प्रधान सचिव, योजना विभाग से अनुमोदित करवाया गया ।

16. जिला योजना अनुभाग

इस अनुभाग द्वारा राज्य स्तर पर जिला योजना स्कीम के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए राज्य सरकार द्वारा 29441.00 लाख रूपये के आबंटन को मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदित करवा कर राशि में से 14500.00 लाख रूपए **SCSP Component** के लिए निर्धारित की गई । वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला योजना की राशी को जनहित तथा राशि को अनुपयोग से बचाने तथा ठीक तरह तथा समयबद्ध उपयोग करने हेतु जिला विकास तथा संचालन समिति का गठन किया गया । यह कमेटी जिले में लोक सम्पर्क तथा शिकायत निवारण कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनीधित्व की जाएगी । इस राशि मे से क्रमशः 10.00 लाख रूपये तथा 50.00 लाख रूपये की दर से प्रति जिला परिषद सदस्य ग्रामीण क्षेत्र तथा प्रति नगर पालिका/पंचायत समिति के हिसाब से निर्धारण करेगी ।

जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि 29441.00 लाख रूपये को 10000.00 लाख रूपये संशोधित किया गया जिसमे से 4902.00 लाख रूपये **SCSP Component** के लिए निर्धारित की गई क्योंकि वर्ष 2012-13 के दौरान केवल तीन महीने का समय बचता था तथा यह निर्णय लिया गया कि बची हुई राशि 19941.00 लाख रूपये को वर्ष 2013–14 के प्रारम्भ में ही जारी कर दिया जायेगा । जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी राशि को प्रयोग करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का संकलन कार्य प्रगति पर रहा ।

17 मूल्यांकन सर्वेक्षण अनुभाग

यह अनुभाग विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करता है ताकि उनके सामान्य प्रभाव, कार्यान्वयन करने में विलम्ब के कारण तथा सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमों का विश्लेषण किया जा सके ।

वर्ष 2012—13 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारन्टी स्कीम, मिड डे मील, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं इन्दिरा आवास योजना की मूल्यांकन रिर्पोटें छपवाने उपरान्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी गई। मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए विभिन्न स्कीमों/विषयों की सूची एवं उनके उद्वेश्य व अन्य विवरण तैयार किये गये।

"Cost of Cultivation of Sugarcane crop and sugarcane Ratoon" विषय पर **Out Sourcing** से मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए **Private Agency** के लिए **Terms of Reference** तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा । नई स्कीम **"Institute for Research and Development"** के अर्न्तगत मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के **Administrative Secretaries** के साथ **Brain storming Meeting** आयोजित की गई जिसमें **Out Sourcing** से मूल्याकंन करवाने वाली योजनाओं एवं विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा सम्बन्धित विभागों को मूल्याकंन अध्ययन करवाने के लिए स्कीमों की सूची भेजने हेतु लिखा गया ।

नई योजना **"Institute for Research and Development"** के तहत मूल्यांकन करवाने हेतु दो **Institute CRRID** एवं **IDC** का चयन करके इन **Institutes** को 5 करोड़ रूपये की राशि **Endowment/corps fund** के तौर पर जारी की गई ।

18. <u>योजना अनुश्रवण अनुभाग</u>

इस अनुभाग का गठन राज्य योजनाओं तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/परियोजनाओं की आर्थिक प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये किया गया है । वार्षिक योजना 2012-13 का प्रस्तावित परिव्यय निर्धारित करने हेतु योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता मे दिनांक 25-4-2012 को दिल्ली मे बैठक का आयोजन किया गया जिसके लिए वार्षिक योजना 2011-12 का संशोधित परिव्यय का 31-3-12 तक के अनुमानित खर्चे की सूचना एकत्रित व संकलित की गई। वार्षिक योजना 2011-12 की चतुर्थं तिमाही (31-03-2012) की वार्षिंक प्रगति रिपोर्ट योजना आयोग, भारत सरकार व सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गई। 27 जुलाई, 2012 को प्रधान सचिव, योजना विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें वितीय वर्ष 2011-12 की प्लान खर्चो की समीक्षा के लिए वांछित सूचना तैयार की गई। माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में 16-11-2012 को उतरी राज्यो के मुख्य मंत्रियों की बैठक हेतु रिपोर्ट तैयार की गई। वार्षिक योजना 2012-13 की जून, सितम्बर व दिसम्बर, 2012 को समाप्त होने वाली त्रैमास की प्रगति रिपोर्ट योजना आयोग, भारत सरकार, वित मंत्रालय व सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गई।

Director-Special Plan योजना आयोग को प्रथम तिमाही तक के खर्चों की सूचना भेजी गई। **ERAMU (FD)** को **Haryana Bureau of Public Enterprises** की वार्षिक योजना 2011-12 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक योजना 2012-13 की 31 दिसम्बर, 2012 तक के वास्तविक खर्चों की रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2013 तक के अनुमानित खर्चों की रिपोर्ट प्रेषित की गई। **ERAMU (FD)** को वार्षिक योजना 2007-08 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की **Centrally Sponsored Schemes** के खर्चों की सूचना उपलब्ध करवाई गई। प्रधान सचिव, योजना विभाग को **Flagship Programme** की मास अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक प्रति मास मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी गई ।

19 मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय अनुभाग

मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय अनुभाग अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के प्रशासन अधीन कार्य करता है परन्तु इसके तकनीकी कार्य का निरीक्षण विशेष कार्य अधिकारी (मानवशक्ति) करता है । इस अनुभाग का मुख्य कार्य तकनीकी व्यक्तियों जैसे कि डाक्टर, अभियन्ता, अध्यापक तथा कृषि विशेषज्ञों की मांग तथा पूर्ति सम्बन्धित अनुमान लगाना है । योजना परियोजनाओं के अधीन रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है । रोजगार विभाग हरियाणा से 30–06–12 को हरियाणा में रोजगाार की स्थिति, कितनी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों ने रोजगार के लिए नाम दर्ज करवाए तथा तकनीकी योग्यता निपुण रोजगार चाहने वालों की संख्या आदि सूचनाओं को एकत्रित किया गया।

अनुभाग द्वारा विभिन्न विभागों से गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम, स्वयं रोजगार स्कीम, प्रशिक्षण व उत्पादन एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 व वार्षिक योजना 2011–12 में स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाये गए रोजगार बारे सूचना एकत्रित की गई । हरियाणा मानव विकास प्रतिवेदन की सूचना तैयार की गई ।

20 राज्य पदर्शन प्रबन्धन सैल (आर0एफ0डी0)

28 मई, 2012 को प्रदर्शन प्रबन्धन प्रभाग,भारत सरकार के सचिव द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर सभी विभागों के प्रदर्शन की निगरानी एवं मूल्याकंन प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की गई तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार योजना विभाग की देखरेख में योजना विभाग में प्रदर्शन प्रबन्धन सैल का गठन किया गया।

जुलाई, 2012 में कैबिनेट सचिवालय के सहयोग से दो दिन की कार्यशाला का आयोजन करवाया गया जिसमें आर0एफ0डी0 की सम्भावनाओं एवं तैयारी से परिचित होने के लिए सभी प्रशासकीय सचिवों ने भाग लिया।

आर0एफ0डी0 तैयार करने हेतू सभी विभागों को राज्य प्रदर्शन प्रबन्धन सैल द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए। एन0आई0सी0 नई दिल्ली से साफटवेयर विकसित करवाया गया। वित्त वर्ष 2012–13 के लिए 39 विभागों से आर0एफ0डी0 का ड्राफ्ट तैयार करवाया गया। 5 सितम्बर, 2012 को दिल्ली में तदर्थ टास्क फोर्स, भारत सरकार से इन आर0एफ0डी0 की समीक्षा करवाई गई। राज्यों के प्रशासकीय सचिवों के साथ तदर्थ टास्क फोर्स, के विचार विर्मश के अनुसार विभागों द्वारा आर0एफ0डी0 संशोधित करवाई गई एवं इसे राज्य सरकार को पुनः प्रस्तुत किया गया। 4 एवं 5 अक्टूबर, 2012 को 6 सिंडिकेट के समूहों में मुख्य सचिव तथा सचिव प्रर्दशन प्रबंधन प्रभाग, भारत सरकार के नेतृत्व में इन आर0एफ0डी0 की भारत सरकार की तदर्थ टास्क फोर्स से पुनः समीक्षा करवाई गई। तदर्थ टास्क फोर्स ने विभागों द्वारा तैयार की गई आर0एफ0डी0 के प्रारूप में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया। इसके पश्चात् विभागों से इन संशोधनों को आर0एफ0डी0 में सम्मिलित करवाया गया।

मुख्य सचिव द्वारा आर0एफ0डी0 की समीक्षा एंव अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिचाई एवं प्रधान सचिव योजना को सदस्य बनाया गया। इस कमेटी द्वारा सभी 39 विभागों से सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों/विभागाध्यक्षों से इन आर0एफ0डी0 की पुनः समीक्षा की गई। आर0एफ0डी0 को अन्तिम रूप देने के लिए समिति की टिप्पणियां विभागों को भेजी गई तथा सभी 39 विभागों की वर्ष 2012–13 की आर0एफ0डी0 को अन्तिम रूप दिया गया तथा इसे मन्त्रीपरिषद से अनुमोदित करवाया गया ।

(ग) <u>जिला सांख्यिकीय एजैंसियां</u>

जिला सांख्यिकीय एजैन्सियां राज्य के सभी 21 जिलों में कार्य कर रही हैं । कार्यक्रमों, परियोजनाओं के निरूपण एवं चल रहे कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए ये एजैन्सियां अभीष्ट आंकडे प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला सांख्यिकीय एजैन्सियों के मुख्य कार्य संक्षिप्त रूप से नीचे वर्णित हैं :–

क– जिले की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर सभी प्रकार के आंकड़ों का संग्रह, संकलन तथा पोषण करना ।

ख– आंकडे प्रदान करने वाली अन्य एजैन्सियों को संग्रह तथा संकलन कार्य के संदर्भो में मार्ग दर्शन प्रदान करना तथा निरीक्षण करना ।

ग– जिला स्तर पर किये जाने वाले सर्वेक्षणों में आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

घ– विभिन्न कार्यालयों में सांख्यिकीय सूचना एकत्रित करने वाले तथा सूचना प्रदान करने वाले कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।

ड– जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना ।

जिला सांख्यिकीय एजैन्सियों द्वारा की जाने वाली नियमित सांख्यिकीय गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

I जिला सांख्यिकीय सारांश

जिला स्तर पर जिला सांख्यिकीय कार्यालय, जिले के विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों को दर्शाने वाले आंकडों का संग्रह तथा सकंलन करने वाली प्रमुख एजैन्सी है । इस विषय पर मुख्य प्रकाशन जिला सांख्यिकीय सारांश है जिसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, कर्मियों का व्यवसाय के अनुसार वितरण, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, साक्षरता, वर्षा, भू–उपयोगिता, फसलों के अधीन क्षेत्र, फसलों का उत्पादन, सिंचित निवल क्षेत्र, सिंचित कुल क्षेत्र, ट्रैक्टर, नलकूप तथा पम्प सैट, वन, पशुधन और पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, परिवहन, सडकें, अपराध, स्थानीय निकाय, पंजीकरण, बैकिंग, सामुदायिक विकास, कीमतें आदि सभी प्रकार के आंकड़ों का समावेश किया जाता है । वर्ष 2012–13 के दौरान जिला सांख्यिकीय सारांश वर्ष 2010–11 सभी जिला सांख्यान कार्यालयों द्वारा तैयार किया गया ।

II कीमत सम्बन्धी आंकडे

जिला सांख्यिकीय कार्यालयों पर मार्किट कमेटियों से कृषि पदार्थो की थोक कीमतों, जिला मुख्यालय नगरों से खुदरा भाव तथा चुने हुए बाजारों तथा औद्योगिक कस्बों से परचून कीमतें एकत्र करने का उत्तरदायित्व है । इन आंकड़ों का प्रयोग राज्य स्तर पर सूचकांक तैयार करने के लिए भी किया जाता है ।

III मण्डी आमद

जिला सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न कृषि पदार्थो के मण्डी आमद सम्बन्धी आंकड़े भी एकत्रित किये जाते हैं । इन आकडों का नियमित रूप से मार्किट कमेटियों से संग्रह किया जाता है तथा उन्हें काल श्रृंखला (टाईम सीरीज) के रूप में रखा जाता है ।

IV नगरपालिका वार्षिक पुस्तक

नगरपालिका वार्षिक पुस्तक में प्रत्येक जिले की नगरपालिकाओं के क्षेत्रफल, जनसंख्या, नगरपालिका के व्यवसाय, वर्षा, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं के महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं । शहरी स्तर की सामाजिक तथा आर्थिक सूचना के लिये यह प्रकाशन बहुत उपयोगी है । वर्ष 2012–13 के दौरान नगरपालिका वार्षिक पुस्तक वर्ष 2010–11 सभी जिला सांख्यान कार्यालयों द्वारा तैयार की गई ।

V 20 सूत्रीय कार्यक्रम

उपायुक्तों एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समितियों द्वारा जिला स्तर पर चल रहे 20–सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति का पुनरीक्षण प्रत्येक माह किया गया तथा जिला सांख्यिकीय एजैन्सियों द्वारा मासिक सूचना तैयार की जाती रही ।

VI जिला सामाजिक आर्थिक पुननिरीक्षण

जिला सामाजिक आर्थिक पुननिरीक्षण वर्ष 2010–11 जिसमें जिला स्तर पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण हैं, सभी जिलों द्वारा तैयार किया गया ।

(घ) <u>जिला योजना कार्यालय</u>

हरियाणा में जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई । इस योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला योजना कार्यालय खोले गये हैं । इनके कार्य की देख रेख जिलों के सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्त करते हें जिनको कि मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है । वर्ष 2007–08 में विकेन्द्रीकृत योजना को समाप्त कर जिला योजना नामक नई स्कीम शुंरू की गई है । ये कार्यालय अपने जिलों में स्थानीय स्तर के विकास के लिए नई स्कीमों को जिले की जिला योजना समिति से अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि से इनको कार्यान्वित करवाते हैं ।

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 में विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन के लिये तथा किये गए कार्यो की प्रगति की समीक्षा के लिये विभिन्न जिला योजना समितियों की बैठक नियमित रूप से बुलाई गई ।

(ड) <u>चौकसी से सम्बन्धित सूचना</u>

उक्त अवधि के दौरान चौकसी विभाग से इस विभाग के कर्मचारियों से सम्बन्धित कोई मामला नोटिस में नहीं लाया गया ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्नक के रूप में आगामी पृष्ठों पर उपलब्ध है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के राजपत्रित तथा अराजपत्रित वर्ग के पदों का विवरण 2012–13 (31–3–2013 की स्थिति अनुसार) ।

(1) मुख्यालयः

पद संज्ञा	पदों की संख्या	
	उपलब्ध पद	भरे हुये पद
(प) राजपत्रित		
निदेशक	1	1
अतिरिक्त निदेशक	2	1
संयुक्त निदेशक	2+1**	2+1**
उप निदेशक	10	7
अनुसंधान अधिकारी	31	24+1@
अधीक्षक	1	1
लेखा अधिकारी	1	1

(ii) अराजपत्रित

सहायक अनुसंधान अधिकारी/छानबीन निरीक्षक	47+2**	27+4 @+2**
सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (र0प0स0)/अन्वेषक	17+3**	7+1@+3**
क्षेत्रीय सहायक	19	9
अवर क्षेत्रीय अनुसंधाता	8+2**	4
कलाकार एंव प्रारूपकार	1	1
उप-अधीक्षक	2	2
सहायक	14	14
लिपिक	12	2+1@
निजी सहायक	2	1
वरिष्ठ आशुलिपिक	6	6
कनिष्ठ आशुलिपिक	7+1**	7
आशुटंकक	20	1
चालक	4	–
मशीन आपरेटर (डुप्लीकेटिंग मशीन)	1	–
मशीन आपरेटर (फोटोस्टेट मशीन)	1	–
सेवक	32	18+1@

2) जिला सांख्यान कार्यालयः

(प) राजपत्रित		
जिला सांख्यान अधिकारी	21	17
(पप) अराजपत्रित		
सहायक जिला सांख्यान अधिकारी	21	20
सांख्यिकीय सहायक / निरीक्षक (र.प.स.)/ अन्वेषक	27	19
क्षेत्रीय सहायक	48	20
अवर क्षेत्रीय अनुसंधाता	40	3
सहायक	21	18+3@
लिपिक	19	11
अनुरेखक	–	3*
सेवक	40	33

(3) जिला योजना कार्यालयः

(i) राजपत्रित		
मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी	19	–
योजना अधिकारी	21	17
(ii) अराजपत्रित		
अनुसंधान सहायक	21	18
कार्टोग्राफर/ज्योग्राफर	–	12*
आशुटंकक	–	–
सेवक	21	19
सहायक	–	–
गैस्टेटनर आपरेटर	–	4*
कुल योग	560+9**	330+11@+19*+6**

@ कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

* अधिक भरे गये पद विभाग की रीस्ट्रक्चरिंग/राईट साईजिंग के कारण हैं तथा ये पद डिमीनिशींग/डाईंग कैडर में रखे गये हैं ।

** आर्थिक गणना स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत पद ।